International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

सामाजिक न्याय की भूमिका के रूप में आर्थिक मुद्दों पर गांधी के विचारो का अध्ययन

LOKENDRA BAHADUR SINGH
RESEARCH SCHOLAR SUNRISE UNIVERSITY ALWAR RAJASTHAN

DR AVANISH KUMAR MISHRA
ASSOCIATE PROFESSOR SUNRISE UNIVERSITY ALWAR RAJASTHAN

सारांश

महात्मा गांधी की अर्थव्यवस्था व अर्थशास्त्र के बारे में बहुत मौलिक सोच थी। यह सोच उस समय के प्रचलित विचारों की परवाह न कर सीधे-सीधे ऐसी नीतियों की मांग करती थी जिससे गरीबों को राहत मिले। साथ ही उन्होंने ऐसे सिद्धांत उपनाने को कहा जिनसे दुनिया में तनाव व हिंसा दूर हो तथा पर्यावरण को नुकसान न पहुंचें। गांधीजी के लिए विश्व शांति, संतोष व पर्यावरण की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण थे। वह इसी के अनुकूल आर्थिक नीतियों की बात करते थे। उन्होंने अर्थनीति और नैतिकता में कभी भेद नहीं किया। गांधी ने स्पष्ट लिख मुझे स्वीकार किया कि मैं अर्थविद्या और नीतिविद्या में कोई भेद नहीं करता। जिस अर्थविद्या से व्यक्ति या राष्ट्र के नैतिक कल्याण को हानि पहुंचती हो उसे मैं अनीतिमय और पापपूर्ण कहूंगा। गांधी ने लिख मेरी राय में न केवल भारत की, बल्कि सारी दुनिया की अर्थ रचना ऐसी होनी चाहिए कि किसी को भी उन्न और वस्त्र के अभाव में तकलीफ न सहनी पड़े। दूसरे शब्दों में हर एक को इतना काम अवश्य मिल जाना चाहिए कि वह अपने खाने-पहनने की जरूरतें पूरी कर सके। यह आदर्श तभी कार्यान्वित किया जा सकता है जब जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं के उत्पादन के साधन जनता के नियंत्रण में रहें। वह हर एक को बिना किसी बाधा के उसी तरह उपलब्ध होने चाहिए जिस तरह कि भगवान की दी हुई हवा और पानी हमें उपलब्ध है। किसी भी हालत में वे दूसरों के शोषण के लिए चलाए जाने वाले व्यापार का वाहन न बनें। किसी भी देश या समुदाय का उन पर एकाधिकार अन्यायपूर्ण होगा। हम आज न केवल अपने इस दुखी देश में, बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी जो गरीबी देखते हैं उसका कारण इस सरल सिद्धांत की उपेक्षा है। प्रायः यही माना जाता है कि निरंतर आर्थिक विकास व वृद्धि से ही दुनिया से गरीबी व अभाव दूर होगी, लेकिन महात्मा

गांधी ने यह पहचान लिया था कि इस तरह के आर्थिक विकास के तहत गरीबी व विषमता बढ़ने की संभावना भी मौजूद रहती है।

मुख्यशब्द- सामाजिक न्याय, गांधी के विचार, आर्थिक मुद्दे, आर्थिक नीति, आर्थिक विकास

प्रस्तावना

गांधीजी के विचारों को शब्दों में बांधना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।महात्मा गांधी के विचारों की सरलता और गहराइयों को समझने के लिए शब्दों का अभाव हो सकता है। भूमंडलीकरण के इस दौर में शहरों की चकाचौंध बढ़ती जा रही है, वहीं गाँवों की सादगी धूमिल होती प्रतीत हो रही है। गांधीजी के विचार हमें दोबारा वहीं गांव की गलियों की सादगी और स्वच्छता में ले जाते हैं जहां गोधूलि बेला का आनंद मिलता है, जिसका अभाव आज की भागदौड़ वाली दुनिया में खलता है।

महात्मा गांधी गाँवों को एक राष्ट्र में उत्पादन की सबसे छोटी इकाई के रूप में देखते थे। चूंकि महात्मा गांधी एक आध्यात्मिक पुरुष थे तो उन्होंने अध्यात्म में जिस गांव की संरचना देखी थी वह रामराज्य से प्रेरित थी।इसमें गाँवों को लोकतांत्रिक रूप से चलाया जाता था, जहां शासक लोगों के हित के लिए काम करता था। सभी को समान अवसर प्रदान किए जाते थे, हिंसा की कोई जगह नहीं थी और जहाँ सभी धर्म और मान्यताओं का आदर किया जाता था। परंतु गांधीजी के इस विचारधारा को एक राष्ट्रवादी हिंदू मानसिकता से जोड़ना ठीक नहीं होगा क्योंकि गांधीजी साथ ही साथ यह भी कहते थे कि "मैं उस राम में आस्था नहीं रखता हूं जो रामायण में है, मैं उस राम में आस्था रखता हूं जो मेरे मन में है।"

महात्मा गांधी जिस भारत की कल्पना करते थे उस भारत में पंचायतों को स्वावलंबी बनाने पर जोर दिया गया था। गांधीजी का मानना था कि भारत कुछ चंद शहरों में नहीं बल्कि अपने 7 लाख गाँवों में बसता है। उनका मानना था कि स्वतंत्रता निचले स्तर से आरंभ होनी चाहिए। 19वीं शताब्दी के ढेरों विद्वानों के लेखों में गाँवों को सुचारु रूप से चलाने की बात कही गयी है। गांधीजी ने उन्हीं विचारों को पुनर्जीवित कर भारत के लोगों के समक्ष रखा था। बापू ने नए सिद्धांतों का आविष्कार नहीं किया था, उन्होंने भारत की

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal
www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

महान सभ्यता से बस पुनः अवगत कराया था।

गांधीजी का कहना था कि "अर्थ पक्ष और नैतिक पक्ष एक दूसरे के पूरक है, अर्थात आर्थिक प्रतिस्पर्धा में हमें अपनी नैतिकता को भूलना नहीं चाहिए क्योंकि प्रकृति के नियम पूर्ण सत्य हैं, परंतु आर्थिक नियम समय व स्थान के साथ बदलते रहते हैं।"

गांधीजी का मानना था कि भारत की सभी समस्याओं का समाधान 'अहिंसा' में छिपा है। गांधीजी पूंजीवाद के विरोधी थे। उनका कहना था कि "इस पृथ्वी पर मानव की आवश्यकता अनुसार प्रचुर मात्रा में संसाधन उपलब्ध है, परंतु मानव की लालसा के अनुरूप संसाधन नहीं हैं"। अगर मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का उपयोग करें तो कोई भी इस दुनिया में भूखा नहीं मरेगा। गांधी जी उन सभी अहिंसक आजीविकाओं के समर्थन में थे जो घृणा और शोषण के विरुद्ध थे।

गांधीजी विकेंद्रीकृत उद्योगों के पक्षधर थे। उनका मानना था कि औद्योगीकरण समस्त सामाजिक राक्षसों की जननी है। गांधीजी ने विकेंद्रीकृत उद्योगों का समर्थन किया क्योंकि उनका मानना था कि विकेंद्रीकृत उद्योगों में शोषण ना के बराबर होगा। चूँकि भारत एक श्रमिक प्रधान देश है और उस वक़्त पूंजी का अभाव था तो ऐसे में श्रम धनिक तकनीक का इस्तेमाल होना चाहिए। ये सिद्धांत आज के समय में प्रासंगिक नहीं लगते हैं परंतु यह उस समय की बात है जब भारत में बेरोजगारी तथा भुखमरी बहुत बड़े स्तर पर थी। उस वक़्त की स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों को सप्ताह में एक बार उपवास करने की सलाह दी जाती थी ताकि सभी लोगों को भोजन उपलब्ध हो सके।

गांधीजी भारत की आर्थिक स्वतंत्रता को निचले स्तर से शुरू करना चाहते थे, इसके लिए गांधीजी ने 'ग्राम सर्वोदय' का नारा भी दिया ताकि गांव अपना उद्धार खुद कर सके तथा 'सर्वोदय- सभी के उदय' की अवधारणा प्रस्तुत हो। भारत के संविधान में ग्राम पंचायतों का गठन इसी विचारधारा से प्रेरित है।

महात्मा गांधी के आर्थिक-विचार

देश की आर्थिक समस्याएँ (गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी, भुखमरी) ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूंजीवादी प्रणाली का विरोध स्वदेशी आदि आर्थिक घटकों की स्पष्ट झलक दिखाई देती हैं। उनका आर्थिक दर्शन राष्ट्रवादी भावना और मानवतावादी दृष्टिकोण पर आधारित हैं। वे साधा जीवन और उच्च सोच वाली धारणा में विश्वास करते थे इसीलिये उन्होंने सर्वप्रथम भारतीय ग्रामों की काया पलट करने हेतु ग्राम स्वराज की अवधारणा पर जोर दिया था। उनका कहना था कि जब तक हम ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु उनको सत्ता का अधिकार प्रदान नहीं करेंगे तब तक सच्चे अर्थों में राष्ट्र का विकास असंभव हैं। इस हेतु उन्होंने पंचायती राज जैसी अवधारणा पर जोर दिया और एक आदर्श ग्राम की परिकल्पना के अन्तर्गत ग्रामों में शिक्षा हेतु स्कूल स्वच्छ आवास व पानी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ बिजली यातायात हेतु सड़के बांध व सिंचाई के साधन इत्यादि गांधी जी के अनुसार - मेरा आदर्श ग्राम बुद्धिमान इंसानों से लड़ेगा वे जानवरों की तरह गंदगी और अंधेरे में नहीं रहते हैं बल्कि सभी प्रयुक्त रूप से जागरूकता प्राप्त करके आदर्श ग्राम की संरचना करते हैं।(3)

गांधी जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करने एवं एक आर्थिक रूप में आत्मनिर्भरता प्रदान करने हेतु लघु व कुटीर उद्योगों को पुर्नजीवित करने की वकालत की थी। उन्होंने श्रम को महत्व देते हुये कहा था कि - देश में पर्याप्त मात्रा में मानव संसाधन अर्थात श्रम उपलब्ध होने के कारण हमें ऐसी अर्थव्यवस्था का पालन करना चाहिये जिसमें अधिक से अधिक श्रम का प्रयोग हो और वह तभी संभव हैं जब हम श्रम गहन प्रौद्योगिकी को अपनाएंगे।

महात्मा गांधी जी के द्वारा दिये गये आर्थिक विचारों पर दृष्टि डालते हैं तो हमें उनके विचारों में देश की आर्थिक समस्याएँ (गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी, भुखमरी) अर्थव्यवस्था का स्वरूप और देश का सर्वांगीण विकास आदि आर्थिक घटकों की स्पष्ट झलक दिखाई देती हैं। उनका मुख्य आर्थिक दर्शन मानव जाति की भलाई तथा राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित हैं। गांधी जी देश तथा मानव जाति की सेवा करके आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं जिसे उन्होंने अपनी रचनात्मक गतिविधियों संगठनों एवं आन्दोलनों के माध्यम से पूर्ण किया था। गांधी जी के अनुसार - "एक व्यक्ति तथा राष्ट्र के लिये

IJARST
International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

आर्थिक आत्मनिर्भरता अपरिहार्य हैं।"(1) हालांकि उनके बारे में यह कहा जाता हैं कि वे न तो अर्थशास्त्री थे और न ही उन्होंने अपने आपको कभी अर्थशास्त्री माना था वे पढ़ाकू नहीं थे लेकिन फिर भी उनके दिये गये आर्थिक सिद्धांत आज भी एक राष्ट्र के संदर्भ में सटीक एवं उचित साबित होते हैं। ग्राम स्वराज ग्रामीण अर्थव्यवस्था, लघु एवं कुटीर उद्योग, विकेन्द्रीयकरण की अवधारणा श्रम समस्याएँ आदि सभी आर्थिक घटकों में उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये आर्थिक दृष्टिकोण न केवल प्राचीन भारत बल्कि वर्तमान भारत के संदर्भ में भी सटीक तथा सही साबित होते हें। यदि गांधी जी न होते तो आज हम जिन लघु एवं कुटीर उद्योगों को देख रहे हैं वह अस्तित्व में नहीं होते क्योंकि आज जैसे-जैसे सम्पूर्ण विश्व एक वैश्वीकरण की अवधारणा में प्रवेश कर चुका हैं वैसे-वैसे बड़े एवं विशाल उद्योगों की महत्ता बढती जा रही हैं या हम यह कह सकते हैं कि वृहत व विशाल उद्योगों का तेजी से विकास होता जा रहा हैं जिसमें श्रम के स्थान पर मशीनों एवं नवीनतम तकनीकी का प्रयोग किया जाता हैं। गांधी जी के आर्थिक विचार भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्रस्तुत किये गये थे। जिनमें मशीनों के लिए कोई जगह नहीं थी क्योंकि उनका मानना था कि इस प्रकार (मशीन) की व्यवस्था से भारत जैसे विकासशील देश में श्रमिकों का शोषण, गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं इसलिये वे मशीन के स्थान पर श्रम को महत्व देते थे। उनका मानना था कि इससे सम्पूर्ण मानव जाति का हित सुरक्षित रहेगा और प्रत्येक देशवासी आसानी से अपना जीविकोपार्जन कर सकेगा, गरीबी का समापन होगा तथा देश उत्तरोत्तर रूप से प्रगति के सोपानों को प्राप्त कर सकेगा।

गांधी जी का आर्थिक दर्शन उस समय की स्थिति का वर्णन करता हैं जब देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और भारत अनेक प्रकार की समस्याओं (भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी) से जकड़ा हुआ था इसीलिये उनके आर्थिक विचारों में न केवल ग्राम स्वराज स्वदेशी कुटीर एवं पारिवारिक उद्योग विकेन्द्रीयकरण जैसे आर्थिक घटकों का समावेश मिलता हैं बल्कि संरक्षणवाद तथा राष्ट्रवादी भावना के भी लक्षण दिखायी देते हैं जो उनके द्वारा दिया गया प्रिय सिद्धान्त अहिंसा पर आधारित थे। गांधी जी मानव की आवश्यकता के अनुसार अर्थशास्त्र का

प्रयोग करने की सलाह देते थे उनके जीवन में फैशन तथा भौतिकवादी या विलासितापूर्ण जीवन यापन के लिये कोई स्थान नहीं था। यही कारण हैं कि उन्हें साधा जीवन उच्च विचार नामक कहावत की परिधि में देखा जाता हैं। 'गांधी वादी अर्थशास्त्र' शब्द गांधी जी के मित्र व समर्थक जे.सी. कुमारण्या द्वारा गढ़ा गया था।

नई सहस्राब्दी में गांधीवादी आर्थिक व्यवस्था

गांधीवादी आर्थिक व्यवस्था सादगी, विकेंद्रीकरण, आत्मनिर्भरता, सहयोग, समानता, अहिंसा, मानवीय मूल्यों, आत्मनिर्भर ग्राम इकाइयों और बुनियादी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण, स्वदेशी और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित है। ये, बदले में, श्रम, पूंजी, उत्पादन, वितरण और लाभ आदि से संबंधित समस्याओं का समाधान करेंगे। 1991 से, हम बाजार-उन्मुख मुक्त आर्थिक प्रणाली का पालन कर रहे हैं लेकिन पुरानी समस्याएं अभी भी हल नहीं हुई हैं और उच्च विकास हासिल करना बाकी है। और इसलिए वर्तमान आर्थिक समस्याओं के लिए कोई अन्य वैकल्पिक समाधान खोजने की तत्काल आवश्यकता है। "गुन्नार मिर्डल और अन्य जैसे विभिन्न अर्थशास्त्रियों की राय है कि गांधी के दिशानिर्देशों का पालन करके भारत और अन्य विकासशील देशों की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को काफी हद तक हल किया जा सकता है।

आत्मनिर्भर ग्राम अर्थव्यवस्था:

गांधी ने घनी आबादी वाले कस्बों में रहने वाले करोड़ों लोगों के खतरों के बारे में चेतावनी दी। शहरीकरण के परिणामस्वरूप कस्बों और शहरों में बढ़ती सघनता और कुछ बहुत अमीरों और बहुत गरीबों के बीच बढ़ती खाई के परिणामस्वरूप एक ऐसा माहौल बन गया है जिसमें अपराध, हिंसा, शोषण शहरी जीवन की एक नियमित विशेषता है। इसलिए, गांधीवादी समाधान यह है कि "प्रत्येक गांव अपनी सभी आवश्यकताओं को प्रदान और उपयोग करे और इसके अलावा शहरों की आवश्यकताओं में अपने योगदान के रूप में एक निश्चित प्रतिशत का उत्पादन करे।"

विकेंद्रीकरण:

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
IJARST
ISSN: 2457-0362

गांधीजी केंद्रीकृत उद्योगों की बुराइयों को दूर करने के लिए लघु-स्तरीय विकेन्द्रीकृत और लघु-स्तरीय सहकारी संगठन में विश्वास करते थे। कुटीर और ग्रामोद्योगों के विकास के माध्यम से आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण कुछ हाथों में आर्थिक शक्ति की एकाग्रता को खत्म करने का एक साधन था। वह बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास से उत्पन्न होने वाली बढ़ती आय और धन असमानताओं के खिलाफ थे। विकास के चरण में लोग सामाजिक न्याय के साथ विकास का लाभ उठा सकते हैं; हर किसी को क्षमता विस्तार और पूर्ण स्वतंत्रता का आनंद लेने का समान अवसर मिलता है।

उत्पादन का पूंजीवादी तरीका:

गांधी के अनुसार विभिन्न कारकों के बीच उपज को विभाजित करने के वर्तमान तरीके भी हिंसक हैं। अपनाई गई तकनीक कारक की एक इकाई को वह हिस्सा देने का प्रयास करती है जो उसके द्वारा किए गए योगदान के अनुसार होता है। स्वाभाविक रूप से यह आय की स्पष्ट असमानताओं को जन्म देता है और उत्पादन की अन्य कम कुशल इकाइयों के लिए बहुत कम हिस्सा छोड़ता है। एक विलासितापूर्ण जीवन जीता है और दूसरा भूखा रहता है। वितरण का यह तरीका हिंसक है और इसे अहिंसक तरीके से बदला जाना चाहिए, जिसमें आय की ऐसी असमानताएं मौजूद न हों। मशीनरी की बुराइयों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गांधी ने कहा, "मैं समुदाय की कीमत पर कुछ लोगों का संवर्धन नहीं करूंगा। वर्तमान में, मशीन एक छोटे से अल्पसंख्यक वर्ग को जनता के शोषण पर जीने में मदद कर रही है।

गांधी जी का दृष्टिकोण:

ग्रामीण भारत की भारी गरीबी, बेरोजगारी और अल्परोजगार की समस्याओं के तत्काल समाधान और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उनकी सामाजिक-आर्थिक योजनाओं के लिए, स्पष्ट विकल्प उत्पादन की श्रम-गहन पद्धति थी। ग्रामोद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में फैल जायेंगे; शहरी उद्योग निजी तौर पर स्वामित्व में हो सकते हैं, लेकिन वे ग्रामीण उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, और भारी, बुनियादी और राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण प्रमुख उद्योग राज्य के नियंत्रण में बिना लाभ और हानि के आधार पर चलाए

जाएंगे, छोटे और बड़े उद्योग प्रत्येक के पूरक होंगे। अन्य। गांधीवादी विकल्प ग्रामीण उद्योगों में स्वरोजगार के माध्यम से जनता द्वारा उत्पादन था।

तरक्की और विकास:

विकास की गांधीवादी अवधारणा बहुत व्यापक थी, जिसमें न केवल आर्थिक विकास बल्कि सामाजिक और मानव विकास भी शामिल था। सभी के मानव कल्याण के बिना आर्थिक विकास बिल्कुल भी विकास नहीं है और इसलिए विकास की गांधीवादी अवधारणा को एक सूत्र में कहा जा सकता है:

विकास = आर्थिक विकास + सर्वोदय

गांधीजी का विचार था कि मानव संसाधन योजना और नीतियों का केंद्र बिंदु होना चाहिए। उन्होंने कहा, "मैं दिल से मानता हूं कि ऐसी कोई भी नीति जो केवल कच्चे माल का उपयोग करती है और शक्तिशाली मानव संसाधनों की उपेक्षा करती है, वह महज बर्बादी है और इस तरह से मानवीय समानता स्थापित नहीं की जा सकती।"

गांधी जी की विकास की अवधारणा देश के सभी लोगों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति पर आधारित है। जब तक गरीबी और बेरोजगारी दूर नहीं हो जाती, गांधी यह मानने को तैयार नहीं हैं कि देश ने वास्तव में समृद्धि और आजादी हासिल कर ली है। गांधी के लिए: "असली संपत्ति में आभूषण और पैसा शामिल नहीं है, बल्कि हममें से प्रत्येक के लिए उचित भोजन, कपड़े, शिक्षा प्रदान करना और रहने की स्वस्थ स्थितियां बनाना शामिल है। एक देश को समृद्ध और स्वतंत्र तभी कहा जा सकता है जब उसके नागरिक आसानी से कमा सकें उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।"

गांधीवादी कार्यक्रम विकास के तीन चरणों को दर्शाता है। ग्रामीण विकास के पहले चरण में, उद्देश्य अधिक रोजगार और आय उत्पन्न करने और समग्र गरीबी के स्तर को कम करने के लिए ग्रामोद्योग और हस्तशिल्प (खादी) के विकास के माध्यम से गांवों का पुनर्निर्माण करना था। मूल विचार गांव को स्वावलंबी और स्वावलंबी बनाना था। गांधीजी हर चीज़ में आत्मनिर्भरता चाहते थे।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर गांधीजी के आर्थिक विचारों का प्रभाव

गांधी चाहते थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने के उद्योगों या उपभोग व्यय के सहारे काम करने के बजाय स्वायत्त ग्राम गणराज्यों के इर्द-गिर्द केंद्रित रहे। अपने आर्थिक विचारों को तैयार करने के गांधीजी के सिद्धांत 'प्रकृति की ओर लौटने' के आह्वान पर आधारित थे। वह चाहते थे कि लोग जीवन में अपनी ज़रूरतें कम करें और आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपनी क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करें। इससे गांवों के लोगों को काम की तलाश में शहरों की ओर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी लोग अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन जिएंगे। वह अर्थव्यवस्था में मशीनों और औद्योगिक उत्पादन प्रणालियों के उपयोग को तभी उचित ठहराएंगे जब परिणाम लोगों की मूलभूत और सबसे बुनियादी जरूरतों को पूरा करेंगे। यह पेपर गांधी के आर्थिक सिद्धांतों का वर्णन करता है ताकि यह विश्लेषण किया जा सके कि वे आज बाजार के मुक्त संचालन से कैसे भिन्न हैं, जिसने समाज में कई नई असमानताएं पैदा की हैं। भारत में उदारीकृत तीव्र आर्थिक विकास मॉडल ने शहरी केंद्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के व्यापार और विनिर्माण में तेजी से वृद्धि के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र के विकास को गौण बना दिया है। यह गांधी द्वारा अपने देश के लिए बताए गए रास्तों के विपरीत चला गया है, और इसने उन्हीं सामाजिक असमानताओं को बढ़ा दिया है जिन्हें वह कम होते देखना चाहते थे।

आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था में गांधीवादी प्रभाव

भारत की स्वतंत्रता के बाद और 1948 में गांधी की मृत्यु के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के कामकाज को प्रभावित करने वाले आर्थिक विचार पश्चिमी और औद्योगिक थे। इसके अलावा, आर्थिक क्षेत्र में राय, तरीकों और रणनीतियों के कई टकरावों ने सरकार के निर्णयों को प्रभावित किया। गांधी के आर्थिक विचारों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक कार्यक्रमों और बाद में स्वतंत्र भारत सरकार के निर्णयों पर स्वतंत्र प्रभाव पड़ा। चूंकि गांधीवादी विचार पश्चिमी आर्थिक विचारों से पूरी तरह से अलग थे, इसलिए भारतीय राजनीतिक नेताओं के लिए यह निश्चित था कि पश्चिम में कल्याणकारी राज्य

की अवधारणाएं और भारत के लिए आर्थिक नीति के बारे में गांधी के विचार अलग-अलग थे। चुनौती दो अलग-अलग अवधारणाओं के दृष्टिकोण में सामंजस्य स्थापित करने की थी, ताकि भले ही स्वतंत्रता के बाद पश्चिमी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का भारतीय आर्थिक योजनाकारों पर अधिक प्रभाव पड़ा हो, गांधी का दृष्टिकोण राष्ट्रीय घरेलू समस्याओं के समाधान के लिए रणनीतियों का मार्गदर्शन करना जारी रख सके। नव स्वतंत्र भारत के आर्थिक योजनाकारों में प्रधान मंत्री नेहरू प्रमुख थे। वह सबसे प्रमुख कांग्रेस नेताओं में से एक थे और गांधी के भरोसेमंद सहयोगी थे। नेहरू को केंद्रीकृत योजना में दृढ़ विश्वास था और वे इसमें सर्वांगीण आर्थिक विकास हासिल करने और भारतीय लोगों को गरीबी से दूर करने का समाधान देखते थे। राष्ट्रीय आर्थिक योजना पर नेहरू का प्रभाव, और उनके विचारों के लिए राजनीतिक नेताओं का समर्थन, 1936 और 1940 की अवधि के बीच कांग्रेस की वैचारिक प्राथमिकताओं में होने वाले परिवर्तनों और पार्टी को एक बहु-दल में बदलने के लिए कांग्रेस के भीतर तनाव के उद्भव का कारण बना। क्लास पार्टी (चक्रवर्ती, 1992)। कोई यह देख सकता है कि आर्थिक नियोजन पर गांधी और नेहरू के विचारों में कोई अंतर नहीं था। दोनों ने देश में "सभी के लिए समान आर्थिक न्याय और अवसर के साथ एक समाज...मानव जाति को उच्च भौतिक और सांस्कृतिक स्तर तक उठाने के लिए" समाज बनाने के लिए समाजवादी योजना शुरू करने का प्रयास किया (चक्रवर्ती, 1992: 281)। भारत में अर्थव्यवस्था के पहिए चलाने वाले मशीनीकृत उद्योगों और बिजली और ईंधन पैदा करने वाली बड़े पैमाने की परियोजनाओं के बारे में नेहरू के दृष्टिकोण ने अधिकांश राष्ट्रीय नेताओं को पसंद किया, जिन्होंने नेहरू के लक्ष्यों को "भारत को शास्त्रीय पुरातनता वाली एक कृषि सभ्यता से एक कृषि सभ्यता में बदलने" के आवश्यक प्रयासों के रूप में देखा।

निष्कर्ष

गांधीजी ने सामाजिक-आर्थिक बुराइयों के रामबाण उपाय के रूप में वकीलों, डॉक्टरों, शिक्षकों और सफाईकर्मियों के लिए वेतन की समानता के क्रांतिकारी सिद्धांत को स्थापित किया। वह रस्किन की मजदूरी की समानता की अवधारणा को सभी प्रकार के

श्रम तक विस्तारित करता है और समान वितरण की वकालत करता है। अतः समाज में समानता लाने में गांधीवादी आर्थिक विचार एवं ट्रस्टीशिप की प्रासंगिकता निश्चित महत्व रखती है। इसके लिए शिक्षा का प्रसार जरूरी है।

गांधीजी के अनुसार, "...जीवन के लिए शिक्षा, जीवन भर शिक्षा, और जीवन भर शिक्षा"। इसका मतलब है कि शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति का अंत उसकी मृत्यु के साथ ही होता है।" गांधीजी ने शिक्षा के अनेक पहलुओं पर अनेक टिप्पणियाँ की हैं। बुनियादी शिक्षा का उनका दर्शन काफी व्यापक है क्योंकि वह शिक्षा को समाज में व्यक्तियों के लिए सामाजिक-आर्थिक प्रगति, भौतिक उन्नति, राजनीतिक विकास और नैतिक विकास के साधन के रूप में देखते हैं। गांधीजी की बुनियादी शिक्षा की अवधारणा पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया है। इसका उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। उनका प्राथमिक जोर 3 आर यानी पढ़ना, लिखना और अंकगणित के बजाय 3'एच यानी सिर, हृदय और हाथ पर है। गांधीजी के लिए, शिक्षा की एक संतोषजनक और सुदृढ़ व्यवस्था के लिए सिर, हृदय और आत्मा का सच्चा विकास आवश्यक है। सच्ची शिक्षा वह है जो आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं को विकसित और उत्तेजित करती है। गांधीजी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य संपूर्ण मनुष्य का निर्माण करना तथा उसके समग्र व्यक्तित्व का विकास करना होना चाहिए। गांधीजी की बुनियादी शिक्षा की अवधारणा मानव व्यक्तित्व में चार गुना विकास, अर्थात् शरीर, मन, हृदय और आत्मा पर जोर देती है। सच्ची शिक्षा व्यक्ति की आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं को उत्तेजित करती है। गांधीजी के अनुसार, सच्ची शिक्षा को मानव विकास के किसी भी क्षेत्र की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। गांधीजी हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि शिक्षा का लक्ष्य केवल अच्छे व्यक्तियों का निर्माण करना नहीं है, बल्कि ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना है जो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को उस समाज के अभिन्न अंग के रूप में समझते हैं जिसमें वे रहते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. दास, धीरज कुमार, "समसामयिक काल में गांधीवादी सिद्धांत की प्रासंगिकता", प्रतिध्वनि: ए जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, असम, 2012।

2. दास, रतन, 21वीं सदी में गांधीजी, नई दिल्ली, सैम्प प्रकाशन, 2003।

3. दास, बी.सी., और मिश्रा, जी.पी., गांधीजी इन टुडेज़ इंडिया, नई दिल्ली, आशीष पब्लिशिंग हाउस, 1979।

4. दत्ता, डी.एम., महात्मा गांधी का दर्शन, विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय प्रेस, 1953।

5. दत्ता मिश्रा, ए और गुप्ता, आर, महात्मा गांधी के प्रेरक विचार: दैनिक जीवन में गांधी, नई दिल्ली, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी, 2008।

6. दत्ता मिश्रा, ए., गांधीवाद आफ्टर गांधी। दिल्ली, मित्तल प्रकाशन, 1999।

7. देवोदास, टी.एस., सर्वोदय और राजनीतिक संप्रभुता की समस्या, मद्रास विश्वविद्यालय, 1974।

8. धीमान, ओ.पी., गांधीजी का विश्वासघात, नई दिल्ली, कल्पाज़ प्रकाशन, 2010।

9. दिवाकर, आर.आर., अहिंसा, दिल्ली, गांधी शांति प्रतिष्ठान, 1968।

10. दिवाकर, आर.आर., महात्मा गांधी 100 वर्ष। नई दिल्ली, गांधी शांति प्रतिष्ठान, 1968।

11. ईश्वरन, एकनाथ, गांधी: द मैन, मुंबई, जैको पब्लिशिंग हाउस, 1997।

12. फिशर, लुईस, गांधी: विश्व के लिए उनका जीवन और संदेश, पेंगुइन ग्रुप (यूएसए) इंक., मास मार्केट पेपरबैक, 2010।